दिनांक 29 अगस्त 2017 को कृषि विज्ञान केन्द्र, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, इन्दौर एवं केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित ''न्यू इंडिया मंथनः संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम'' के आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

1. मुझे आज यहां कृषि विज्ञान केन्द्र में आप सबके बीच उपस्थित होकर अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वर्ष 1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प लिया था ''भारत छोड़ो'' का और वर्ष 1947 में वह महान संकल्प सिद्ध हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। उसी संकल्प से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक एक ''न्यू इंडिया'' के निर्माण का संकल्प लिया है और ''संकल्प से सिद्धि अभियान'' की शुरूआत की है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा 16 अगस्त से 30 अगस्त 2017 तक ''न्यू इंडिया मंथनः संकल्प से सिद्धि'' कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में आयोजित किया जा रहा है।

2. यहां मैं यह संदेश देना चाहती हूं कि गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, आतंकवाद जैसी बुराइयों के विरूद्ध जनमत का निर्माण करने के उद्देश्य से एवं आम जनता को साथ लेकर ही आगे बढ़ना सरकार का लक्ष्य है क्योंकि किसी भी कार्यसिद्धि में आम जनता को साथ लेकर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

3. जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि युगों–युगों से आजीविका के साथ–साथ भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती आई है। हमारे वैदिक मंत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि इनके माध्यम से हम प्रकृति की पूजा–अर्चना एवं आराधना करते थे और यह हमारे आध्यात्मिक जीवन दर्शन, संस्कृति एवं परम्पराओं में अभी भी शामिल है। इनमें कुछ परम्पराएं कृषि संस्कृति से जुड़ी हुई हैं जिनका वर्णन हमें वेदों में मिलता है।

ऋषि पराशर ने कृषि पराशर नामक पुस्तक के श्लोक–8 में लिखा है:–

''कृर्षिधन्या कृषिर्मेध्या जन्तूनां जीवनं कृषिः।''

(अर्थात् कृषि सम्पत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है।)

4. कृषि क्षेत्र अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और आज भी यह भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार देने वाला (लगभग 55 प्रतिशत) क्षेत्र है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान लगभग 17 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार ने कृषि संसाधनों के सतत् प्रबंधन के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

5. हमारे देश में महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण जैसे चिंतक हुए हैं जिन्होंने भारत की आत्मा को समझा है, अन्नदाता को समझा है एवं उनकी समस्याओं और समाधान पर अपने विचार दिए हैं एवं उनके कल्याण को महत्वपूर्ण माना है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं एवं वर्ष 2022 तक उनकी आय को दोगुना करना सरकार का लक्ष्य है जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की है। आज इसका संकल्प लें तभी तो पांच वर्ष पश्चात् हम इसे सिद्ध कर सकेंगे। इसमें सभी किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, राज्य एवं केन्द्र सरकारों सहित सभी नीति–निर्माताओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

6. मैं मानती हूं कि बड़ी जोत वाले किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तो ठीक है परंतु छोटे और सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्हें सस्ते दर पर बीज, खाद एवं आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के साथ–साथ सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हें सम्मानित जीवन एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि दिलाने के उद्देश्य से सभी ओर से सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है।

7. आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश में लगभग 56 प्रतिशत खेती योग्य क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं एवं कुल खाद्य उत्पादों का 44 प्रतिशत उत्पादन इस rain fed area से होता है। भविष्य में देश को कृषि की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के सभी भागों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है।

8. पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए कृषि से संबंधित सभी आयामों को सुदृढ़ करने एवं उनका आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। अधिक खाद्यान्न उत्पादन के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं अवसर प्रदान करने से आर्थिक विकास में तेजी आती है और इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे न केवल घरेलू खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलती है बल्कि किसान का जीवन स्तर भी सुधरता है।

9. परंपरागत पद्धतियों और ज्ञान को एकत्र करने और इसका मूल्यांकन करने तथा सतत् कृषि विकास के लिए इनका उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और पंचायत स्तरों पर संगठित प्रयास किए जाने चाहिएं। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि का विविधीकरण करते हुए उन्हें मधुमक्खीपालन, पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन और पुष्पोत्पादन और फलों के बगीचे लगाने, तिलहनों और दालों, कपास और आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे आय और आजीविका के साथ–साथ जीवन स्तर में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। अतः, हमें इसके लिए गैर–परंपरागत एवं नवोन्मेषी सोच (Innonvative Ideas) को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें जन जागरूकता विकसित करने में स्व–सहायता समूहों के कार्य को मान्यता देनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

10. एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 32.8 प्रतिशत महिलाएं खेती में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं। खेती के एक सीजन में महिलाएं आमतौर पर 3300 घंटे

खेत में गुजारती हैं जबकि पुरुष आमतौर पर 1860 घंटे खेत में गुजारते हैं। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं महिलाओं की कृषि में हिस्सेदारी को स्वतः प्रमाणित करते हैं।

11. मैं तो यह भी सोचती हूं कि महिलाएं बड़े पैमाने पर जब कृषि कार्यों में लगी हैं, तो उनकी सुविधा के अनुसार कृषि उपकरण का निर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादकता में भी पर्याप्त वृद्धि संभव हो सके।

12. खाद्य सुरक्षा कृषि उत्पादन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है तथा सतत् भूमि एवं जल प्रबंधन खाद्य सुरक्षा के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, निर्धनता में कमी, कृषि उत्पादन, वितरण, विपणन, ऋण और अन्य कारकों को भी खाद्य सुरक्षा के अभिन्न भाग के रूप में स्वीकार किए जाने की जरूरत है।

13. आज ऐसी फसलें उगाने के लिए शोध आवश्यक है जिन पर सूखे, कीट पतंगों और रोगों का प्रभाव न पड़े। कीट प्रबंधन, स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक सामग्री का अधिक प्रभावी रूप से उपयोग, बदल–बदल कर फसलें उगाने की पद्धति और कृषि वानिकी सहित बारहमासी फसलें कृषि उत्पादन में सुधार लाने और अंततः किसानों की आय में वृद्धि के लिए आवश्यक है।

14. हम सब जानते हैं कि जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया गया था। डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने से भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। कृषि के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने से सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों, मौसम की जानकारी, बाढ़ की चेतावनी, बाजार मूल्य, मिट्टी क्षेत्र के अनुकूल कृषि जानकारी का आदान–प्रदान शीघ्र किया जा सकता है।

15. वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए हमें सात सूत्रीय फार्मूला पर कार्य करना होगा। सर्वप्रथम उत्पादन में वृद्धि लाने की दिशा में हमने सिंचाई एवं जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं को अगले 4 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस वर्ष लगभग 5 लाख

नए तालाब बनाने का लक्ष्य है। ''Per Drop More Crop योजना'' के तहत पांच हजार करोड़ रुपये के Longterm Irrigation Fund (लांगटर्म इरिगेशन फंड) से अब उन एरिया में भी सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा सकेगा, जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचता था।

16. दूसरे, हमें सर्वश्रेष्ठ बीजों एवं पोषकता पर ध्यान देना होगा। उर्वरकों का सीमित उपयोग, जैविक खेती के लिए योजना को शीघ्र लागू करने एवं नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हमें अधिकतम पैदावार सुनिश्चित करने की ओर प्रयत्न करना होगा। घर से निकलने वाले green waste को कम्पोस्ट खाद के रूप में उपयोग कर न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जा सकता है बल्कि स्वच्छ वातावरण के साथ–साथ उच्च उत्पादकता हासिल की जा सकती है।

17. सभी 648 कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए मिनी स्वॉयल टेस्टिंग लैब का प्रावधान किया गया है जो मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करेगा एवं यह पता लगाएगा कि मिट्टी की दशा कैसी है एवं कौन–सी फसल वहां उपजाई जा सकती है।

18. उपज के बाद सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उत्पाद को सुरक्षित रख नहीं पाते हैं। इस उद्देश्य से ''किसान सम्पदा'' योजना भी प्रारंभ की गई है जिससे food processing industries, warehouse और cold storage की स्थापना होने लगी है।

19. कृषि उत्पादों के अवशेषों (bye products) को नवोन्मेषी तरीके से (innovative ways) उपयोग कर क्या हम स्टार्ट अप इंडिया के तहत कोई छोटा उद्यम स्थापित कर सकते हैं क्या? आप लोग इस दिशा में सोचें एवं संबंधित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों से सलाह लें।

20. किसानों के लिए बेहतर बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में बाजार की स्थापना, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी बाजार यार्ड के बाहर प्रोसेसर/निर्यातकों/थोक खरीददारों आदि द्वारा सीधी खरीद, किसान उपभोक्ता सीधा बाजार, अनुबंध खेती आदि जैसे प्रगतिशील कदम प्रावधानित हैं। किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाजेशन के रूप में संगठित किया जा रहा है ताकि उन्हें न सिर्फ उनके उत्पादों का सही मूल्य मिले बल्कि व्यापारियों के समक्ष उनकी सौदेबाजी शक्ति भी बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए, उत्पादों की बिक्री के लिए बाजारों का एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेटफार्म (e-NAM प्लेटफॉर्म) बनाया गया है। देश भर में स्थित 585 मंडियों को इससे जोड़ने की योजना है और अब तक 250 मंडियों को इससे जोड़ दिया गया है। इससे किसानों को एक ही प्लेटफार्म पर कई खरीदार मिल सकते हैं और वह सही मुनाफे पर अपनी फसल बेच सकता है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की 58 मंडियों को जोड़ा गया है जिसमें से इन्दौर और महू भी हैं। इस कार्य हेतु प्रत्येक मंडी को basic infrastructure develop (स्वच्छता ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग) करने के लिए 75 लाख रुपये प्रति मंडी की दर से फंड प्रदान की जाएगी।

21. केवल फसल उपजाना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उन्हें बेचना भी जरूरी है। इसके लिए आधुनिक तकनीक के बारे में युवा किसान भी जानें एवं अपने बुजुर्गों को इसके बारे में बताएं ताकि फसल का optimum price मिल सके।

22. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसानों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। पहले जहां आधी फसल खराब होने पर आपदा राहत राशि देय होती थी अब वह एक तिहाई नुकसान पर भी देय है। किसान हित में आपदा राहत दरों में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में और गति लाते हुए इस वर्ष 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को इस योजना के तहत लाए जाने की योजना बनाई गई है जो किसानों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करती है।

23. किसानों की आर्थिक समृद्धि एवं उनके समग्र विकास के लिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के साथ–साथ Blue Revolution (नीली क्रांति) की योजना बनाई गई है, जिसके तहत अंतरदेशीय मत्स्यपालन के साथ–साथ Deep Sea Fishing पर भी विशेष ध्यान दे रही है। अब तो sweet revolution यानि शहद उत्पादन में बढ़ोत्तरी की भी योजना बन रही है। आप सब भी इसका लाभ उठा सकते है।

24. ''मेड़ पर पेड़'' कैम्पेन के तहत सरकार खेतों के मेड़ों पर वृक्षारोपण की दिशा में एक नई पहल कर रही है जिसमें उस पेड़ के पूर्ण विकसित होने पर उसके व्यावसायिक उपयोग की अनुमति भी किसानों को दी जाएगी। इससे भी किसानों की आय बढ़ेगी।

25. मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि केन्द्र और राज्य सरकार ने किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, पर इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को ही जागरूक होकर आगे आना होगा एवं उन योजनाओं का लाभ उठाना होगा। तभी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुना करने का हम सबका संकल्प सिद्ध हो सकेगा।

26. यह जागृत होने एवं योजना को कार्यान्वित करने का समय है। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए ''न्यू इंडिया'' के संकल्प का यह सही समय है। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे, जहां सभी के पास पक्का घर होगा, बिजली होगी, पानी होगा। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे, जहां देश का किसान चिंता में नहीं, चैन से सोएगा, आज वो जितना कमा रहा है, उससे दोगुना कमाएगा। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां युवाओं और महिलाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे। हम गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, जातिवाद मुक्त तथा सम्प्रदायमुक्त भारत का संकल्प लेते हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा

भारत बनाएंगे जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा।

27. हम सब वर्ष 2022 तक सभी किसानों की कृषि आय दोगुना करने, आय सुरक्षा के लिए फसलों के बीमा का, माटी की सेहत के लिए जैविक खेती अपनाने का एवं सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने का संकल्प लेते हैं। हम सब उच्च पैदावार के बीज एवं रोपण सामग्री, एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने का एवं कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन के साथ–साथ उसके सही एवं सुरक्षित भंडारण का संकल्प लेते हैं।

28. सन् 1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प लिया था ''भारत छोड़ो'' का और वर्ष 1947 में वह महान संकल्प सिद्ध हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। अब हम सब मिलकर अगले पांच सालों में यानी सन् 2022 तक एक ''न्यू इंडिया'' बनाने का संकल्प लेते हैं।

जय हिन्द।